भारत का फार्मा निर्यात 7 .38 प्रतिशत बढ़ा

ड्रग फॉरमुलेशंस और जैविक उत्पादों का दबदबा

सीडीएमओ और एफडीआई को मिलेगा बढ़ावा

अप्रैल-मई में निर्यात 4 .9 अरब डॉलर पहुंचा

नयी दिल्ली, 02 जुलाई. फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के ताजा अपडेट के अनुसार, भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-मई अवधि में सालाना आधार पर 7.38 प्रतिशत बढ़कर 4.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है.

फार्मेक्सिल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक अधिकृत एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है.देश के फार्मा सेक्टर का बढ़ता हुआ निर्यात दिखाता है कि इंडस्ट्री के उत्पादों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है. फार्मेक्सिल ने कहा कि यह वृद्धि स्थायी विनिर्माण, वैश्विक बाजार में उपस्थिति में विस्तार और डिजिटल इनोवेशनों पर केंद्रित रणनीतिक पहलों के कारण आई है और साथ ही बताया कि ये प्रयास भारत के फार्मा उद्योग के लिए एक ट्रिलियन डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मजबूत कर सकते हैं.

फार्मेक्सिल के चेयरमैन नमित जोशी ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा, भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में सालाना आधार पर लगातार वृद्धि जारी है और निर्यात श्रेणी में ड्रग फॉरमुलेशंस और जैविक उत्पादों का वर्चस्व बना हुआ है. जोशी ने आगे कहा, हम इस वृद्धि का श्रेय बढ़ती वैश्विक मांग, सुव्यवस्थित विनियामक अनुमोदन, टेक्नोलॉजीकल इनोवेशंस, रणनीतिक साझेदारियों और आर्थिक स्थिरता को देते हैं. भारत के फार्मा निर्यात में मई में ड्रग फॉरमुलेशंस और जैविक उत्पादों की हिस्सेदारी 75.74 प्रतिशत रही है.

> **भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते से इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा**
>
> जोशी के अनुसार, भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा. इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में वृद्धि होगी और सस्ती दवाओं तक पहुंच में सुधार होगा. यह विशेष रूप से अनुबंध विकास और विनिर्माण (सीडीएमओ) और संयुक्त अनुसंधान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा.

2030 तक भारत बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था

हरदीप पुरी बोले - जर्मनी को पीछे छोड़ेगा भारत

2030 तक जर्मनी को पछाड़ने का लक्ष्य

नयी दिल्ली, 02 जुलाई.केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इस क्रम में 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था को लेकर तीसरे पायदान पर आने की ओर अग्रसर है.

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ग्यारहवीं से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. केंद्रीय मंत्री पुरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के 77वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कहा, हमारी जीडीपी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो कि 2014 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है.

केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक चुनौतियों के दौरान देश की मजबूती और साहसिक नीति सुधारों, व्यापक सामाजिक कल्याण योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि प्रमुख सामाजिक पहलों के तहत 27 करोड़ से अधिक नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है.

विनिर्माण पीएमआई 14 माह की ऊंचाई पर

मजबूत निर्यात मांग से उत्पादन में तेजी

जून पीएमआई बढ़कर 58 .4 के स्तर पर पहुँचा

नयी दिल्ली, 02 जुलाई.एक व्यावसायिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की विनिर्माण गतिविधि जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो अंतरराष्ट्रीय बिक्री में पर्याप्त वृद्धि से प्रेरित थी, जिसने उत्पादन को बढ़ावा दिया और रिकॉर्ड-तोड़ भर्ती को जन्म दिया.

एस एंड पी ग्लोबल द्वारा संकलित एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मई के 57.6 से बढ़कर जून में 58.4 पर पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह जारी प्रारंभिक अनुमान के अनुरूप है. पीएमआई का 50.0 का स्तर गतिविधि में वृद्धि और संकुचन को अलग करता है.

एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, मजबूत अंतिम मांग ने उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार सृजन में विस्तार को बढ़ावा दिया. मजबूत मांग के समर्थन से फैक्ट्री उत्पादन पिछले साल अप्रैल के बाद से सबसे तेज गति से बढ़ा.

आने वाले नए ऑर्डर लगभग एक साल में सबसे तेज दर से बढ़े, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मांग ने महत्वपूर्ण गति प्रदान की. निर्यात ऑर्डर ने मार्च 2005 में डेटा संग्रह शुरू होने के बाद से तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की, जिसमें अमेरिकी बाजारों को अक्सर ताकत के स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया.यह सकारात्मक आंकड़े अमेरिकी शुल्कों से बढ़ती अनिश्चितता के बीच आए हैं.

> मजबूत मांग ने निर्माताओं को अभूतपूर्व गति से अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया - यह सर्वेक्षण शुरू होने के दो दशक से अधिक समय में सबसे तेज गति है .जून में निर्माताओं के लिए मूल्य दबाव कम हुआ, जिसमें इनपुट लागत मुद्रास्फीति चार महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई, हालांकि लोहा और इस्पात की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई . ऐतिहासिक रुझानों की तुलना में यह नरमी महत्वपूर्ण थी .

एमपी-सीजी में जियो का दबदबा

जियो फाइबर और एयर फाइबर को मिले 54 हजार से ज्यादा यूजर

भोपाल,02 जुलाई.टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस जियो ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल में एक बार फिर सबसे ज्यादा मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े हैं. यह उपलब्धि जियो को दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर बनने की ओर अग्रसर करती है.

मई 2025 में रिलायंस जियो से 4.2 लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े, जबकि जियो फाइबर और एफडब्ल्यूए जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को 54 हजार से अधिक ग्राहकों ने अपनाया. इसी अवधि में, एयरटेल के 8 हजार मोबाइल ग्राहक बढ़े, वहीं बीएसएनएल के 37 हजार और वोडाफोन-आइडिया के सर्वाधिक 56 हजार मोबाइल ग्राहक घटे.

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में कुल मोबाइल ग्राहक 8.1 करोड़ से अधिक और एफडब्ल्यूए/वायरलेस ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 24.9 लाख से ज्यादा हैं. इसमें जियो के मोबाइल ग्राहक 4.6 करोड़ और ब्रॉडबैंड ग्राहक 13.9 लाख से कहीं अधिक हैं. मोबाइल में जियो की बाजार हिस्सेदारी 56.7 प्रतिशत और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाता में 56.1 प्रतिशत है.फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस घरों व दफ्तरों में वाई-फाई सर्विस को संदर्भित करता है.

डॉलर के मुकाबले रुपया नौ पैसे फिसला

मुंबई, 02 जुलाई.स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया नौ पैसे टूटकर 85.68 (अस्थायी) पर बंद हुआ.विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में मामूली सुधार से भी रुपये पर दबाव पड़ा क्योंकि बाजार निवेशक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए बातचीत जारी है.अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 85.59 पर खुला. इसने कारोबार के दौरान 85.57 के उच्चस्तर तथा 85.75 के निचले स्तर को छुआ. अंत में यह 85.68 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की गिरावट है.

भारत में ईटीएफ का शानदार उछाल

5 साल में एयूएम 5 गुना बढ़ा, खुदरा निवेशक 11 गुना बढ़े

नयी दिल्ली, 02 जुलाई.भारत में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) ने पिछले पांच वर्षों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इनकी कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति पांच गुना से अधिक बढ़ गई है, जबकि खुदरा निवेशकों के फोलियो में ग्यारह गुना की वृद्धि हुई है.

ज़ेरोधा फंड हाउस द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2020 से मार्च 2025 के बीच भारत में ईटीएफ का कुल एयूएम लगभग 5.5 गुना बढ़कर 8.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह कुल 65.74 लाख करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड उद्योग का लगभग 13 प्रतिशत है, जबकि 2020 में ईटीएफ की हिस्सेदारी केवल 7 प्रतिशत थी. यह देश में एक निवेश विकल्प के रूप में ईटीएफ की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.

ईटीएफ योजनाओं में खुदरा फोलियो की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है - मार्च 2020 में 23 लाख से बढ़कर मार्च 2025 में लगभग 2.63 करोड़ हो गए हैं. अब 97 प्रतिशत से अधिक ईटीएफ फोलियो खुदरा निवेशकों के हैं, जो आम निवेशकों के बीच ईटीएफ के प्रति जागरूकता और विश्वास में तेज वृद्धि को दर्शाता है.

आर .के . गुप्ता बने पावरग्रिड पश्चिम-I प्रमुख

नागपुर, 02 जुलाई,राजेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र-I के सेवानिवृत्त होने के बाद आर.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी), ने आज पावरग्रिड पश्चिमी क्षेत्र-I के क्षेत्रीय प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है.गुप्ता 1994 से पावरग्रिड से जुड़े हुए हैं और उन्हें विद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव है.

उन्होंने संगठन में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया और लोड डिस्पैच एवं संचार,स्मार्टग्रिड, ए सी सबस्टेशन संचालन एवं अनुरक्षण, निर्माण प्रबंधन समूह, पीई एसएम, तथा प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है.उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता से पावरग्रिड की परिचालन उत्कृष्टता और पश्चिमी क्षेत्र-I में विश्वसनीय विद्युत पारेषण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत होने की उम्मीद है.

कोयला उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार

नयी दिल्ली, 02 जुलाई. कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से जून 2025 में कोयला उत्पादन 15.57 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया, जबकि कोयला प्रेषण 17.31 एमटी रहा.वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में साल-दर-साल मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है. इस अवधि में उत्पादन में 16.39त्न और प्रेषण में 13.03त्न की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक है. मंत्रालय ने इस सकारात्मक प्रवृत्ति का श्रेय क्षेत्र में बढ़ी हुई परिचालन दक्षता और खनन क्षमता के बेहतर उपयोग को दिया है. मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में प्रदर्शन में लगातार सुधार पर भी प्रकाश डाला.

सस्ती स्टील डंपिंग पर रोक

13 जून के आदेश से गुणवत्ता और क्षमता निर्माण को बल

स्टील उत्पादों पर बीआईएस मानकों का अनुपालन अनिवार्य

नयी दिल्ली, 02 जुलाई (वार्ता) इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस्पात उत्पादों के संबंध में पिछला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अगस्त 2024 में जारी किया गया था और उसके बाद कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि मध्यवर्ती उत्पाद और उत्पादकों के लिए 13 जून का आदेश घरेलू उत्पदकों के साथ समान व्यवहार, डंपिंग की रोक तथा देश में इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्यों के अनुरूप है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पहले 151 बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के मानकों के प्रवर्तन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं उसके बाद कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण ओदश जारी नहीं किया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, 'इस्पात मंत्रालय के गत 13 जून के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि बीआईएस मानकों के तहत अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए मध्यवर्ती सामग्री, इस्पात उत्पादों को भी ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों के लिए निर्धारित बीआईएस मानकों का पालन करना होगा। कोई नया गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया गया है।' मंत्रालय ने 13 जून के आदेश से देश में इस्पात की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि यह आदेश घरेलू उत्पादकों के साथ समानता के व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

> मंत्रालय ने कहा है कि तैयार इस्पात उत्पादों का आयात तैयार इस्पात उत्पादों के भारतीय निर्माताओं के बराबर नहीं था, क्योंकि भारतीय इस्पात उत्पाद निर्माताओं को केवल बीआईएस मानक के अनुरूप मध्यवर्ती सामग्री का उपयोग करना पड़ता था, जबकि आयातकों द्वारा इस्पात उत्पादों के आयात के लिए ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती थी।

कर्नाटक में कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर

डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री ?

बेंगलुरु. कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एच ए इकबाल हुसैन ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को अगले दो से तीन महीनों के अंदर राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है. शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले विधायक की यह टिप्पणी इस साल के उत्तरार्द्ध में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच आई है.

हुसैन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने सितंबर के बाद राज्य में ''क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रम का हाल में संकेत दिया था. रामनगर में यह पूछे जाने पर कि क्या शिवकुमार के पास मुख्यमंत्री बनने का मौका है, तो हुसैन ने कहा, ''आप सभी जानते हैं कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हमारी (कांग्रेस की) ताकत क्या थी. इस जीत को हासिल करने के लिए किसने संघर्ष किया, पसीना बहाया, मेहनत की और किसकी दिलचस्पी थी, यह सभी जानते हैं. उनकी (शिवकुमार की) रणनीति और कार्यक्रम अब इतिहास बन चुके हैं.

उन्होंने कहा, ''मैं अटकलों पर विश्वास नहीं करता. हमें पूरा विश्वास है कि आलाकमान स्थिति से अवगत है और उन्हें मौका देने के लिए सही समय पर उचित निर्णय लेगा. शिवकुमार कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष भी हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवकुमार इस साल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हुसैन ने जवाब दिया, ''हां, मैं यह कह रहा हूं. सितंबर के बाद क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रम के लिए कुछ नेता जिस तारीख का संकेत दे रहे हैं - वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं. दो से तीन महीने के भीतर फैसला हो जाएगा.

ढाई साल वाला फार्मूला- मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे एवं कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) यतींद्र सिद्धरमैया द्वारा मुख्यमंत्री बदले जाने को महज अटकलें बताकर खारिज करने के बारे में पूछे जाने पर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार

> **राजनीति में बदलाव आम बात**
>
> उन्होंने कहा, ''क्रांति का क्या मतलब है? राजनीति में बदलाव आम बात है. समय आने पर आलाकमान तय करेगा कि किसे जिम्मेदारी दी जाए. आज की परिस्थितियों में अच्छा प्रशासन देने में सक्षम उपयुक्त व्यक्ति को मौका मिलेगा और वह अपना कर्तव्य निभाएगा. बदलाव की उम्मीद तो है, लेकिन इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता. इस बात की ओर इशारा करते हुए कि कांग्रेस पहले से ही सत्ता में है, हुसैन ने दावा किया, ''यदि कोई अन्य पार्टी इस सरकार को उखाड़ फेंकती, तो उसे क्रांति कहा जा सकता था. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है - सरकार मजबूत है और उसके पास स्पष्ट बहुमत है. कांग्रेस के भीतर कई सत्ता केन्द्र होने के बारे में राजन्ना के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ''केवल एक ही सत्ता का केन्द्र है- पार्टी आलाकमान.

झामुमो के भरोसे कांग्रेस की राजनीति !

रांची. झारखंड में झामुमो सुप्रीमो व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तालमेल की कमी है. क्योंकि गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के द्वारा विरोधाभासी बयान सामने आ रहे है.

इस बीच झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, तब तक झारखंड का संथाल परगना कांग्रेस पार्टी के साथ है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का राजनीतिक वजूद ,झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे पर टिका है.

दरअसल सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संथाल की धरती ऐतिहासिक है और संथाल के लोग गुरुजी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार करते हैं. उन्होंने कहा कि बाकी की पार्टी वहां के लोगों को छलने का काम करती है, लेकिन संथाल के लोग को छल नहीं पाती है. तभी तो संथाल के 18 में से 17 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है. उन्होंने कहा कि संथाल के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी और हेमंत बाबू को प्यार करते हैं, और जो भी पार्टी हमारे साथ है उनके साथ है, संथाल उसके साथ भी है. एक तरह से उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इसलिए संथाल में चुनाव जीत पाई क्योंकि वह झामुमो के साथ है और जब तक कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, तब तक संथाल परगना भी कांग्रेस के साथ है. यानी झामुमो के भरोसे संथाल में कांग्रेस की राजनीति टिकी हुई है.

> **झामुमो की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार**
>
> झामुमो की टिप्पणी पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा का कहना है कि हम दोनों गठबंधन में हैं और सिक्के के दो पहलू हैं. एक भी पहलू निकल गया तो फिर सिक्का खोटा हो जाएगा. उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि संथाल परगना में हमारा वजूद है, हमारी पार्टी के द्वारा कई सीटों पर जीत दर्ज की गई है. उन्होंने झामुमो के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, यह महागठबंधन की एकता के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन इसीलिए जीता ,क्योंकि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और अन्य दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था.

विशेष सहनी के पुराने साथी ने बनाई नई पार्टी

बिहार की राजनीति में नई एंट्री

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है. ऐसे में बिहार में सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं. इस बीच कई बड़े नेता भी अपनी पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं.

बिहार से ही एक और बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है. विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के सहायक रहे प्रदीप निषाद ने भी अपनी पार्टी बना ली है. उन्होंने अपनी पार्टी का नाम विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी) रखा है.

शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदीप ने घोषणा की कि यह पार्टी शोषितों, पीड़ितों, दलितों, महादलितों, अत्यंत पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए समर्पित रहेगी.

उन्होंने दावा किया कि इस पार्टी में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि खासकर निषाद समाज की सभी उपजातियों को एक सूत्र में बांधकर उनके वाजिब हक और अधिकार दिलाने की दिशा में पार्टी काम करेगी. यवाओं और महिलाओं को नेतृत्व में बड़ी भूमिका दी जाएगी.

बीरेन के बिना भाजपा का गुजारा नहीं

बीरेन सिंह के हिसाब से होगा मुख्यमंत्री का फैसला

इंफाल. भारतीय जनता पार्टी को दो साल लग गए थे एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से हटाने में और अब साढ़े चार महीने हो गए उनके हटे हुए तब भी भाजपा वहां सरकार नहीं बना पा रही है.

सोचें, मणिपुर में बीरेन सिंह का क्या मतलब है? पहले उनको हटाने के लिए भाजपा के सर्वशक्तिशाली नेतृत्व को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा यानी सीधे उनके हाथ से किसी दूसरे नेता के हाथ में सत्ता ट्रांसफर नहीं किया जा सके. हालांकि तब विधानसभा निलंबित रखी गई ताकि नई सरकार बनाई जा सके. भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले केंद्रीय गृह सचिव रहे अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल बना कर मणिपुर भेजा ताकि प्रशासन और राजनीति दोनों संभले. राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है. बताया जा रहा है कि नई सरकार बनाने का हर प्रयास एन बीरेन सिंह रोक दे रहे हैं. बहुसंख्यक मैती समुदाय में उनकी गजब लोकप्रियता है और भाजपा उनकी अनदेखी करके नया मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है.